[Shri Jairam Ramesh]
at the answer. I want to ask the hon. Minister: Why is he reluctant to make public, or, at least, to Members of Parliament, the list of commodities, which is asked for by the hon. Member?

Use of chemicals and fertilizers in agriculture

*130. SHRI SANJAY SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) the details of use of fertilizers and chemicals in agriculture;

(b) the steps taken for control of their use, if any; and

(c) the plan to increase the use of natural manures?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Under the Fertiliser (Control) Order, 1985. 170 fertilisers have been notified under various categories such as Straight nitrogenous fertilisers, Straight Phosphatic fertilizers, Straight Potassic fertilisers, Micronutrient fertiliser, NP and NPK complex fertiliser, fortified fertiliser, Beneficial element fertiliser 100% water soluble complex, and mixture of fertiliser. Customised fertiliser, Biofertiliser, Organic fertiliser and non edible deoiled cake.

The total consumption of the major fertilizers namely Urea, Di-ammonium Phosphate, Muriate of Potash. Complex and Single Super Phosphate during last three years and the current year is as under:

Year	Consumption (in LMT)
2016-17	536.11
2017-18	543.82
2018-19	562.09
2019-20*	349.36

* Estimated sales upto October, 2019.

There are 939 pesticides listed in schedule of the Insecticides Act, 1968. Till date. 292 technical and 736 formulations are registered as pesticides for use in the country.

Government of India has been promoting soil test based Integrated Nutrient Management (INM) *i.e.* balanced and judicious use of fertilisers through Soil Health Card Scheme since 2014-15. Soil Health Cards provide information to farmers on nutrient status of their soil along with crop wise recommendation on appropriate dosage of nutrients to be applied for improving soil health and fertility.

The concept of Integrated Pest Management *i.e.* biological, cultural and mechanical methods of pest control has also been promoted through Central Integrated Pest Management Centres (CIPMCs) across the country. These Central IPM centres educate the farmers about judicious use of chemical pesticides and recommend the use as per the directions prescribed on the label claim and leaflets and as last resort.

Government of India has been promoting the production and use of organic fertilizers/natural manures under various programmes such as Capital Investment Subsidy Scheme (CISS), Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), and Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER).

Market Development Assistance @ ₹ 1500/- per metric ton (MT) has also been provided to Pertiliser Companies for sale of City Compost.

Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has developed improved technology for preparation of bio-enriched compost, vermin compost, city compost, bio-gas slurry manure etc. from various rural, urban and agro-industrial bio-wastes.

श्री संजय सिंह: महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के जवाब में पूछा था कि फ़र्टिलाइज़र्स के उपयोग को कम करने की सरकार की क्या योजना है, जिससे लागत कम हो। मंत्री जी का जवाब खुद यह बताता है कि हर वर्ष फ़र्टिलाइज़र्स का उपयोग घटने की बजाय बढ़ रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो योजना बतायी है, ज़मीन पर उसका असर देखने को क्यों नहीं मिल रहा है और इसका उपयोग कम क्यों नहीं हो रहा है?

श्री परशोत्तम रुपाला: सभापति महोदय, यह बात सच है कि उर्वरकों की उपयोगिता में बढ़ोतरी दिख रही है, किंतु उर्वरकों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किसान करें, यही हमारे विभाग की मंशा है। हम किसानों में उसके प्रति अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते अभी पिछले महीने हमारे विभाग ने और उर्वरक मंत्रालय ने साथ मिलकर किसानो का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में किसानों को यह बताने की कोशिश की गई थी, और आप जिन कार्यक्रमों का ज़िक्र कर रहे हैं, जैसे कि सॉयल हैल्थ कार्ड वगैरह, उसी के ज़रिये हम किसानों को यह जताना चाहते हैं कि आप ऐसी ही परम्परा से खेत में खाद डाल रहे हैं, इसके

[श्री परशोत्तम रुपाला]

बजाय आपकी जो साइंटिफ़िक एडवाइज़ हैं, उसी पर आप निर्भर रहते हुए खाद का नियंत्रित रूप में उपयोग करें। यह बताने का अवेयरनेस कार्यक्रम बड़े पैमाने पर देश में हम चला रहे हैं।

श्री संजय सिंह: महोदय, मेरा दूसरा सवाल भी इसी से संबंधित है। जैविक खेती, जिसकी चर्चा आज बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की क्या योजना है?

श्री परशोत्तम रुपाला: महोदय, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु हमारे दो प्रोग्राम चल रहे हैं। यदि कोई ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र बनाना चाहता है तो हम राज्य सरकार को 100 परसेंट सब्सिडी देकर, उसको दो सौ टन तक के यूनिट डालने के लिए सहायता दे रहे हैं। ऐसे ही किसानों को, यदि वे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो उनको 50 हज़ार रुपये, दो हैक्टेयर की लिमिट के लिए, तीन साल तक देने का प्रावधान भारत सरकार की ओर से हम कर रहे हैं।

श्री सभापति: क्वेश्चन 131, कृषि और रेलवे दोनों के ऊपर सब प्रश्न पूछ रहे हैं।

किसानों को ऋण-जाल से मुक्त कराने के लिए कदम उठाये जाना

*131. **श्री राकेश सिन्हा**: क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने किसानों को महाजनों के ऋण-जाल से मुक्त कराने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं;

(ख) वर्ष 2017-18 और 2018-19 में कितने किसानों को महाजनों की उच्च ब्याज दर से मुक्त कराया गया है;

(ग) क्या सरकार किसानों के लिए सहकारी बैंक स्थापित करने का विचार रखती है, जो विशेष रूप से ऋण, उत्पादन और बिक्री से जुड़े मामलों में किसानों की मदद कर सकें; और

(घ) वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में कितने किसानों ने ऋण के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत सरकार द्वारा किसानों/व्यक्तियों की कर्जदाताओं सहित गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए उन्हें संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: